15. NICH. LESLI ASIA, SINGAPORE
16. PAN A HARRISON, SINGAPORE
17. SWIFREBLANCK, SINGAPORE
18. TYSER & CO., U.K
19. WILLCON INC., USA
20. WILLS FABER, U.K.

INDIAN BROKERS

1. DIRECTLY PLACED BY GIC THEMSELVES
2. BHAICHAND AMOLUK, MUMBAI
3. EQUIP ENGINEERS, INDIA
4. GLOBAL INSURANCE SERVICES, MUMBAI, INDIA
5. HOWDEN DASTUR, MUMBAI, INDIA
6. INTERLINK REINSURANCE CONSULTANCY, MUMBAI, INDIA
7. J.B. BODA AND CO. PVT. LTD., ' "MUMBAI, INDIA
8. L. R. RAO, MUMBAI, INDIA
9. M.B. BODA AND CO. PVT. LTD., MUMBAI, INDIA.
10. MATHRAWAA AND SONS, MUMBAI, INDIA
11. R.N. SETH & ASSOCIATES, DELHI, INDIA.

महिलाओं के लिए अलग से न्यायालय

*53. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए गुजरात में कुछ महिला न्यायालयों की स्थापना करने के संबंध में गंभीरता से विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किन-किन शहरों में ऐसे न्यायालय स्थापति किये जाने की संभावना हैं और क्या राज्य सरकार ने कहा हैं कि वह इस प्रयोजनार्थ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायेगी;

(ग) इस समय राज्य में महिलाओं से संबंधित कितने मामलों के संबंध में सूचना मिली हैं; और

(घ) महिलाओं को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) गुजरात में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए महिला न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन, राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता हैं । यह संबद्ध राज्य सरकार/उच्च न्यायालय पर निर्भर करता हैं कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसे न्यायालय की स्थापना करे और महिलाओं से संबंधि मामलों का भी अभिलेख रखें।

Resentment amongst Central Government Employees over recommendation of Fifth Pay Commission

*54. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that resentment is prevailing amongst the group 'D', 'C and 'B' Central Govemment employees as the hike in their salaries is very less as compared to the employees of higher categories in the recommendations of the Fifth Central Pay Commission;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Govemment propose to modify the report of this Commission keeping in view the agitation launched by the Central Govemment employees in the country; and

(d) if so, the steps taken by Govemment to remove this disparity so as to maintain reasonable gap between these categories?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Some associations/Unions of the Central Govemment Employees have represented to the Govemment against certain recommendations of the Commission, including the recommendation relating to the revision of pay scales.

(c) and (d) The Govemment have set up an Empowered Committee of Secretaries to process the recommendations of the Commission. The views of the employees will be ascertained through the National Council of Joint Consultative Machinery and will be kept in view while taking decisions on the recommendations of the Commission.